मांग की थी कि आने वाले एशियन गेम्स के लिये जो स्पोर्ट्स के लिये सामान खरीदा है... ! उसके लिये पांच प्रमुख देशों को देश के अन्दर आने के लिये बाध्य किया जा सकता है बशर्ते कि बारह करोड़ का सामान हम उन से खरीद करें। क्या यह सही है कि भारत सरकार ने ट्रेड फेयर आथोरिटी के इस आग्रह को, इस निवेदन को ठुकरा दिया है और एशियन गेम्ज के लिये जितना सामान खरीदा गया है उस के लिये डैलीगेशन देश से बाहर भेजा गया है जिस पर लाखों रुपया खर्च हुआ है और सारी परचेजिज बाहर से की गई है? क्या यह सही है कि सरकार की इस नीति की ट्रेड फेयर आथोरिटी आफ इंडिया के चेयरमैन ने आलोचना भी की है जिस के सामाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए है?

**श्री शिवराज वी० पाटिल** : इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके लिये मुझे नोटिस चाहिये। जो सामान की खरीद होती है वह दूसरी मिनिस्टरी की ओर से होती है। ट्रेड फेयर आथोरिटी ने उन से मालम किया है या नहीं किया है, मुझे मालूम नहीं है।

### कपड़े की सप्लाई के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम को रक्षा मंत्रालय की ओर से टेंडर

*23. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रक्षा मंत्रालय ने 30,20,300 मीटर कपड़े की सप्लाई के लिये राष्ट्रीय कपड़ा निगम को 8 दिसम्बर, 1981 को टेंडर संख्या बी/89181/डी० जी० आई०/स्टोर-4-पोलियस्टर काटन ओलिवग्रीन जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम यह कपड़ा सप्लाई कर रहा है और क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड ने उन्हें तथा पूर्ति और निबटान महानिदेशालय की सिफारिश की है कि यह टेंडर किसी दूसरे मिल को, अन्तरित कर दिया जाये और यदि हां, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम को कितने करोड़ रुपये की हानि होगी और प्राइवेट मिल को कितना लाभ होगा; और

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड द्वारा टेंडर स्वीकार किये जाने के बाद कपड़ा सप्लाई न करने के क्या कारण हैं और क्या तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

(a to (c): Ministry of Defence floated an Open tender enquiry for the supply of 3.02 million metres of Polyester Cloth for Army units. Since it was considered feasible for N.T.C. to supply the entire quantity of cloth, the N.T.C. requested that Ministry to place the order on NTC. In two instalments, the entire order was placed on the N.T.C. N.T.C. expected that a sizeable portion of the Order would be produced and supplied by its mills in Bombay. However, since the entire Bombay mill industry has been on strike and because the initial problems in stabilising supplies were more than what was anticipated, N.T.C. has not been able to keep to its supply schedule to the Defence Department. The M/O Defence and N.T.C. have been in continuous dialogue to ensure supply of the contracted quantity from N.T.C. to Defence.

**श्री कृष्णचन्द्र पांडे** : अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था लेकिन मंत्री महोदय ने उसका गोल मटोल उत्तर दिया है जिस का

कोई मतलब नहीं निलकता है । उन्होंने उत्तर दिया है कि बम्बई में स्ट्राइक चल रही है इस वजह से हम रक्षा मंत्रालय को कपड़े की सप्लाई नहीं कर पाए । उन्होंने कहा है कि एन टी सी को दो किश्तों में कपड़े की सप्लाई रक्षा मंत्रालय को करनी थी । जवाब दिया गया है कि अभी तक एक भी मीटर कपड़ा सप्लाई नहीं हुआ है इस वास्ते क्योंकि बम्बई में स्ट्राइक चल रही है । मैं जानना चाहता हूं कि कब तक रक्षा मंत्रालय को इस कपड़े की सप्लाई कर दी जाएगी ?

**श्री शिव राज वी0 पाटिल :** बड़ा अजब सवाल हाउस में पैदा हो गया है । मैं डिफेंस मिनिस्टरी में था जब यह आर्डर एन टी सी को दिया गया था और यहां आ कर वह कपड़ा सप्लाई करने का काम भी हमीं को करना पड़ रहा है ।

**अध्यक्ष महोदय :** तब ख्याल नहीं था कि आप यहां आ जाएंगे ।

**श्री शिवराज वी0 पाटिल :** वह कपड़ा गवर्नमेंट के कबजे में जो मिलें हैं, फैक्ट्रियां हैं उन से लेने के लिए हम ने दिया था । बहुत सा आर्डर बम्बई की मिलों को दिया गया, एक तिहाई हिस्सा हमारे आर्डर का बम्बई की मिलों में बनना जरूरी था । लेकिन बम्बई की मिलों में स्ट्राइक होने की वजह से एक तिहाई कपड़ा बनाने में हमें दिक्कत हुई । कम अज कम अठारह लाख मीटर कपड़ा अभी तक बन चुका है । उस में से सात लाख मीटर कपड़े में रंग देने का जो काम है वह बम्बई में हो चुका है । इंस्पैक्शन का काम डिफेंस मिनिस्टरी की तरफ से होता है । जब इंस्पैक्शन होता है तो कभी कभी वे कह देते हैं कि कपड़ा दुरुस्त नहीं है, रंग दुरुस्त नहीं है । यह देखना जरूरी होता है कि जो उनकी मांग है वह हम पूरी तरह से मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं । इसको देखना जरूरी होता है । अगर उस प्रकार का कपड़ा नहीं बन रहा है तो दूसरा बना कर देना पड़ेगा । जिस प्रकार का कपड़ा उनको चाहिये उस प्रकार का पकड़ा बना कर देना जरूरी है । यह सही है कि जिस प्रकार से आर्डर की पूर्ति होनी चाहिये उस प्रकार से नहीं हुई है । कुछ दिक्कते हमारे सामने जरूर आई है और उनको हम देख रहे हैं और दूर कर रहे हैं और पूरा कपड़ा तैयार करके डिफेंस मिनिस्टरी को देने का हम प्रयास कर रहे हैं । हमारा कर्त्तव्य है कि उनको कपड़ा जल्दी से जल्दी हम दें । ऐसी बात नहीं है किएक मीटर भी कपड़ा नहीं बना है । या उसको रंग नहीं दिया गया, या उनको देने की हमने कोशिश नहीं की, यह बात सही नहीं है । मगर इस्पेक्शन में जो अड़चने आ रही हैं उसको दूर करने के लिये और एक सिस्टम बनाने के लिये, क्योंकि दोनों विभाग सरकार के ही हैं, हम उनसे मिल कर रास्ता निकालना चाहते हैं ।

**श्री कृष्णचन्द्र पांडे :** मंत्री जी ने कहा कि 18 लाख मीटर कपड़ा बन गया और उसमें से 7 लाख मीटर कपड़े की रंगाई हो गई । तो मैं जानना चाहता हूं यह जो कपड़े की रंगाई हो रही है वह कौन करा रहा है और किस दर पर हो रही है ? और क्या यह सच नहीं है कि ऐन०टी०सी० ने और उसके कुछ अधिकारियों ने बिन्नी मिल्स लिमिटेड से समझौता किया है और वार्त्ता की है कि इस कपड़े को 48 रु० प्रति मीटर के हिसाब से ऐन०टी०सी० के माध्यम से उसके नाम पर सप्लाई किया जाय ? यदि हां, तो इससे कितने रुपये की क्षति रक्षा मंत्रालय को उठानी पड़ेगी ?

**श्री शिवराज वी० पाटिल :** सवाल यह है कि पहले हमने आर्डर डिफेंस मिनिस्ट्री से दिये और लिए । वह आर्डर पूरे करने का हमने प्रयास किया । मगर स्ट्राइक और दूसरी दिक्कतों की वजह से वह आर्डर वक्त पर पूरा नहीं कर सके जब हमें यह पता चला तो हमने रक्षा मंत्रालय से परमीशन मांगी कि क्या दूसरी फैक्ट्रीज से बनवा कर दें । तो उन्होंने हां कही । उसके बाद बिन्नी मिल्स लिमिटेड को

दिया गया । और यह प्राइवेट कन्सर्न होने पर भी इसके अन्दर सबसे ज्यादा पैसा स्टेट बैंक का और दूसरे पब्लिक फाइनेंशियल कोरपोरेशन्स का है और फोर आल प्रैक्टिकल परपजेज....

**श्री कृष्णचन्द्र पांडे :** 1 करोड़ 91 लाख 75 हजार का नुकसान रक्षा मंत्रालय को हो रहा है । अध्यक्ष जी, आप प्रश्न देख लीजिये, उसका उत्तर पहले गोलमटोल दिया, लेकिन सप्लीमेंटरी में मंत्री जी ने स्वीकार किया है । 1 करोड़ 91 लाख 75 हजार का नुकसान रक्षा मंत्रालय को होने जा रहा है ।

**श्री शिवराज वी० पाटिल :** माननीय सदस्य जो सवाल उठा रहे हैं उसका पूरा जवाब सुन लें तो उनके मन में कोई अस्पष्टता नहीं रहेगी । मैं कह रहा था उनसे हमने परमीशन ली और लेने के बाद, हमारी कुछ फैक्ट्रीज स्ट्राइक की वजह से बन्द हैं और वक्त पर काम नहीं हो सकता, उनसे परमीशन लेने के बाद बिन्नी मिल्स को आर्डर दिया गया । और जो आर्डर दिया गया उसका एक कारण यह भी था कि पूरी तरह से गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंस्टीटयूशन्स से वह मिल कंट्रोल्ड है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स से कंट्रोल्ड नहीं है, बल्कि हमारे इंस्टीट्यूशन्स से कंट्रोल्ड है, इसलिये उनको आर्डर दिया गया । और जो आर्डर दिया गया किस प्रकार से दिया गया ? 49 रु० प्रति यार्ड से अपनी मिल से बनाकर देते थे तो उनसे 48 रु० पर ले कर उनको दे रहे हैं । इसका मतलब यह है कि अगर हम कपड़ा बना कर डिफेंस मिनिस्ट्री को देते तो उसमें एक पैसे का भी उन्हें नुकसान नहीं होता । लेकिन चूंकि अपनी मिल्स में नहीं बना रहे हैं, उनकी तरफ से बनाकर उनको दे रहे हैं । अब इनका कहना यह है कि पहले 44 रु० के हिसाब से बनाकर देने को कहा गया था, अब 48 रु० पर दिया जा रहा है, इसलिये 4 रु० का फर्क आ गया जिससे उनको टोंटा है । तो जब पब्लिक अंडरटेकिंग काम करने के लिये आ जाती हैं तो दूसरे लोग भी आ जाते हैं, और जब ऐसा पता चलता है कि पब्लिक अन्डरटेकिंग्स को ही आर्डर दिया जा रहा है तो दूसरे लोग भी सामने आते हैं और कम दाम भी कोट करते हैं जिससे तकलीफ होती है । यही सब देखने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जितना पैसा ऐन टी सी० को जाने वाला था उससे एक भी पैसा ज्यादा नहीं दिया जा रहा है ।....

**श्री कृष्णचन्द्र पांडे :** अध्यक्ष महोदय, ऐन०टी०सी० को प्राइस प्रीफरेंस है 10 परसेंट । और बिन्नी को कोई प्राइस प्रीफरेंस नहीं है ।

**श्री शिवराज वी० पाटिल :** मैं उनको बताना चाहता हूं कि बिन्नी मिल्स पर तमिलनाडू और कर्नाटक गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स हैं ।....स्टेट बैंक का पैसा उसमें है, पब्लिक अंडरटेकिंग का पैसा उसमें हैं और उसका स्वरूप प्राइवेट होने के बावजूद भी पूरी तरह से कंट्रोल पब्लिक सेक्टर में है । इसके बाद भी डिफैन्स मिनिस्ट्री का जितना पैसा एन०टी०सी० को देना पड़ता है, उससे एक भी पैसा ज्यादा नहीं देना पड़ता है । इसके बावजूद भी अगर माननीय सदस्य ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कुछ करोड़ रुपये का नुक्सान हो रहा है, तो उसमें समझ की गलती हो सकती है ।

**श्री कृष्णचन्द्र पांडे :** अध्यक्ष महोदय, उत्तर साफ नहीं हुआ है । बिन्नी का पहला टेंडर दिया गया था, उसमें 44 रुपये 60 पैसे रेट था ।

**अध्यक्ष महोदय :** सारा उत्तर आ गया है ।

**श्री कृष्णचन्द्र पांडे :** वह 42 रुपये पर होना चाहिये लेकिन ऐसा नहीं किया गया । रक्षा मंत्रालय को फ्रेस टेंडर मांगने चाहिये थे । इस तरह से बिन्नी को 1 करोड़ 91 लाख 75 हजार रुपये का फायदा पहुंचाया गया है और रक्षा मंत्रालय को नुकसान किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : अस्पष्टता हो तो फिर बता दीजिये ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : Sir, I am just explaining to him so that he may not have any misunderstanding in his mind.

यह जो सदस्य कह रहे हैं कि बिन्नी को फायदा हो गया है, उसमें कोई फायदा नहीं हुआ है। अभी कपड़ा बिन्नी की तरफ से सप्लाई नहीं हुआ है। अगर सब चाहते हैं तो कोई दूसरा दृष्टिकोण लिया जा सकता है, पर उससे यह होने वाला है कि डिफेन्स मिनिस्ट्री को जो कपड़ा वक्त पर पहुंचना चाहिये, उसमें देरी हो सकती है। एक पैसे का भी नुक्सान नहीं होना चाहिये। उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, may I know from the hon. Minister:

(a) Is it not a fact that the Textile Commissioner, Bombay permitted an import of polyster yarn by Cotton Textile Mills and others, as actual users, against the policy of the Government, on the instructions of the Joint Secretary (Textiles), New Delhi and collected an amount of Rs. 1,53,00,000 from M/s. Bombay Dyeing Mills which happened to be the prime beneficiary in this case?

(b) Is it also not a fact that the above deal was leaked to Shri Ashutesh Mukherjee, Inspector, Textiles Committee?

(c) Is it also not a fact that Shri Ashutesh Mukherjee was harassed, terrorised and made to commit suicide?

MR. SPEAKER: Does it come out of this Question?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: An inquiry should be instituted into this. *(Interruptions.)*

MR. SPEAKER: Does it arise out of this Question? Does it relate to this Question?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Yes, Sir. It is a fact. *(Interruptions.)*

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: If a Textile Inspector was treated in this way and there is no solution, what does it mean?

AN HON. MEMBER: The culprit should be brought to book. *(Interruptions.)*

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: This does not arise out of this Question. However, if the hon. Member is very keen about knowing as to what is the position with respect to the question which he has put, I can give him the information. But, at present, I do not have the information, because it is not directly connected with the Question. *(Interruptions.)*

AN HON. MEMBER: What about the Joint Secretary who is supposed to have collected.... *(Interruptions.)*

SHRI GHULAM NABI AZAD: Is there somebody else other than Parliament to discuss this question?

MR. SPEAKER: No.

*(Interruptions.)*

SHRI GHULAM NABI AZAD: These Secretaries have got this question disallowed. *(Interruptions.)* I had put this question for yesterday. But they in collusion with some officers** got it disallowed. You cannot put it in Parliament! You cannot raise it in Parliament! Is there somebody else other than Parliament to raise this? This is the bureaucracy! *(Interruptions.)*

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: There should be an enquiry into what he has said. It is a very serious matter. *(Interruptions.)*

SHRI GHULAM NABI AZAD: Some officers * * have got it disallowed. allowed. You should enquire into this. This is a fact.

**Expunged as ordered by the Chair.

MR. SPEAKER: Mr. Azad, this is not the way. Order, order. Please, Order.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Here is a letter also written to the police by the person who has committed suicide and the case is registered in Calcutta. (*Interruptions.*) The letter is written in Bangla and the translation in English is here.

SHRI GEORGE FERNANDES: Let him lay it on the Table of the House. (*Interruptions.*)

MR. SPEAKER: Mr. Azad, you should do it in a proper manner. This is not the way.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Unless I examine it, how can I say?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: There are allegations against the Lok Sabha Secretariat.

MR. SPEAKER: That is what I want to understand.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: You find out.

MR. SPEAKER: That is what I say. I cannot do a thing without investigating it. I must satisfy myself. If there are any allegations which are true, I must proceed against. I will take action. I will look into it.

(*Interruptions*)

SHRI GEORGE FERNANDES: Let him lay the document on the Table of the House.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I will have it investigated. We will find out.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: This letter came in the newspapers also. The *Indian Express* has published the story.

(*Interruptions*)

SHRI JAGDISH TYTLER: Are the Secretaries so powerful that they are controlling the Parliament also?

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: No question. It can be seen; it can be rescinded, anything can be done. It is all right. Certain things can happen. They can be remedied also. There is no problem like that. (*Interruptions*) You can write to me, not like this. I am not going to allow.

(*Interruptions*)

SHRI RAM JETHMALANI: You should not discourage it.

MR. SPEAKER: I am not discouraging. Shri Indrajit Gupta.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Sir, I was not aware of these extremely serious allegations which, I hope, will be properly looked into.

MR. SPEAKER: I will.

SHRI INDRAJIT GUPTA: I am asking a supplementary directly arising out of the replies given by the hon. Minister. He has admitted several things. He said that one-third of the orders were placed with the NTC mills in Bombay. So, we presume from this that the remaining two-thirds of the orders were placed somewhere outside Bombay. He has not stated where they were placed. The NTC mills in Bombay number about 17. The total number of NTC mills in this country is about 130 spread over various States. We would like to know, if one-third of the orders were placed with the NTC mills located only in Bombay, which were the NTC mills in other States where the remaining two-thirds orders were placed.

I am asking this because he has made much of the Bombay strike. He said that the tender was floated on 8th December, 1981 and the strike commenced on 18th January, 1982. That means, even if we assume, as the hon. Minister said, that due to the strike this part of produc-

tion could not be maintained, that affects only 17 NTC mills and only one third of the supply. We do not know what happened to the remaining two-thirds supply for which orders were placed, we assume, on other NTC mills about which he has not told us anything.

Secondly, I want to know why that part of the order which could not be fulfilled were given to the Binnys. The argument put forward here is that because public sector money is invested in the Binnys, it cannot be considered to be a private concern. It is a new definition. I do not know. Now-a-days, you see the industrial policy changing so much rapidly every day that it is very difficult to keep up with it. Tomorrow, we will be hearing that the Tata Iron and Steel Company is not a private sector because the share-holding by the Tatas is only in a minority and that the major share-holding is by the public sector financial institutions and banks. Is that a new definition of our industrial policy?

I would like to know, when you found that you could not maintain production to meet one-third of the supply due to Bombay strike, why did you not give the remaining two-third orders to other public sector NTC mills instead of giving them to the Binnys? Why is this special favouritism shown to the Binnys because that new definition it not being a private sector concern but a public sector concern—is not according to the industrial policy that we have followed all these years? That is why an allegation is being made by my young friends and that, I think, adds to the suspicion that there was some other extraneous consideration as to why the Binnys alone were favoured by it.

The NTC mills have been saddled with the whole responsibility of producing the standard cloth, that is, the controlled cloth for the poor people as a result of which they are making only losses, not profits. The private sector mills were relieved from this responsibility. At least if this Defence order was given to the NTC mills, they could have made a little money on it. Why has it been given to the Binnys instead of giving it to other NTC mills?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: The NTC mill in Maharashtra North and the NTC mill in Maharashtra South were ordered to produce 9.75 lakh metres, the NTC Mill in Gujarat 4.10 lakh metres, the NTC Mill in Tamil Nadu 8.60 lakh metres, the NTC Mill in Andhra Pradesh 3 lakh metres, the NTC Mill in M.P. one lakh metres, the NTC Mill in U.P. 1.80 lakh metres, and the NTC Mill, DPR, 2 lakh metres. The entire order was placed on NTC mills and on none else.

The reasons why one-third of the order was placed on Bombay mills was, the Bombay mills are a little more modernised and we were under the impression that the Bombay mills would be able to produce the cloth in time or before time. So, the major portion of the order was given to the NTC mills in Bombay. Let us not go with the impression that the rest of the orders was given to private mills. Initially, ab initio, no order was given to the private mills, but when it was found that it was not possible for the NTC mills to produce the cloth to meet this order, this step was taken and that too, how much order is given to Binny? Only four lakh metres, and even if it is not to be produced in Binny mills, we can dispense with that also. There is nothing in that. Here on the one hand we are trying to see that the entire order is given to the NTC mills, and in spite of the objections taken by so many people, this order was given. Now when we find that it has not been possible because of certain extraneous reasons, we are trying to see that we meet the orders. I do not think there is anything wrong in that.

If some other question has cropped up and if the Members are a little agitated on that, we do not want to hide anything from the House, but let it come properly before the House. If it comes before the House, we will explain everything to the Members of this august House. There is absolutely nothing which we want to hide. But if the matter is not brought to the notice of the Minister and you expect

him to make the statement on the floor of the House and at the same time you can hold him responsible for committing breach of privilege, he would be between Scylla and Charybdis. We would expect you to put the question in the proper form and we will answer it properly. In this case there is no irregularity made, and if the House thinks that this is not to be done, we can abide by your order.

MR. SPEAKER: Next Question. (*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Sir, please allow an half-an-discussion on this

MR. SPEAKER: We shall have to see.

Next Question.

**Checking Evasion of Central Excise Duties**

+

*24. SHRI B. V. DESAI:

SHRI H. N. NANJE GOWDA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have formulated a new scheme to intensify efforts to check evasion of Central Excise duties;

(b) if so, what ways and means have been planned by Government to check evasion of Central Excise duties;

(c) whether the anti-evasion machinery has been streamlined; and

(d) if so, how far it will be more effective in detecting Central Excise duties?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

(a) An Action Plan to check evasion of Central excise duty has been formulated for implementing Point No. 19 of the 20-Point Programme.

(b) It is planned to improve co-operation and co-ordination between the different investigative and enforcement agencies and the sister Departments, like, Income-tax and Sales Tax etc. Survey of commodities and areas prone to evasion and exempted units, is to be undertaken. Control over the production units is to be tightened. It is proposed to strengthen the anti-evasion machinery and take legal and other measures necessary for effectively checking evasion of central excise duties.

(c) Anti-evasion machinery has been sareamlined and various measures for strengthening it further are under consideration.

(d) It is expected that intensification of antievasion efforts and strengthening of anti-evasion machinery would result in detection of excise duty evasion of higher order.

SHRI B. V. DESAI: In answer to my question regarding checking of evasion of Central excise duties, he has mentioned that some action plan has been envisaged and it is being formulated. But no salient features of that action plan have been given in that. Secondly, the Conservatio of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Act was passed in 1974. It is high time that Government takes a second look at it and tries to plug the loopholes which are existing there. While the Government claims that they have found out 500 kgs. of gold or Rs. 40 crores or some such thing, I can tell them that smuggling is not done in kgs. but in tonnes. They should open their eyes and see that the loopholes in the Act are plugged. That is exactly the case in respect of evasion of Central excise duties. There are different aspects of taxation. Evasion is one thing which is very rampant. Not only is there smuggling but there is evasion of Central excise duties in the country itself. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether Government is proposing to investigate into that and see that the loopholes in the Act are plugged.

SHRI SAWAI SINGH SISODIA: My friend, Mr. Desai, has suggested many other things which are beyond the scope